<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249138 CG-DL-E-04102023-249138

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] No. 258] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3,2023/आश्विन 11,1945

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्याः ए डी(ओआई) -21/2023

विषय: चीन जन.गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए "सॉफ्ट फेराइट कोर" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/22/2023-डीजीटीआर.— 1. कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड (बाद में "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक याचिका दायर की है। , जैसा कि समय-समय पर संशोधित (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी जाना जाता है) और सीमा शुल्क टैरिफ (चोट के निर्धारण के लिए डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित किए गए "सॉफ्ट फेराइट कोर" (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग

6235 GI/2023 (1)

जांच शुरू करने के लिए समय (बाद में इसे "नियम" या "एडी नियम" भी कहा जाएगा) "), चीन जन.गण. में उत्पन्न या निर्यात किया गया (इसके बाद इसे "विषय देश" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

- 2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषयगत वस्तु का भारत में आयात किया जा रहा है, विषयगत देश से उत्पन्न या निर्यात किया जा रहा है, जो डंप कीमतों पर है, जिससे उसे भौतिक क्षति हो रही है और वास्तविक क्षति का खतरा है और उसने अधिरोपण का अनुरोध किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क।
- क. विचाराधीन उत्पाद
- 3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सॉफ्ट फेराइट कोर" है जो चीन जन.गण. में उत्पन्न या निर्यात किया गया है। फेराइट कोर फेराइट से बने चुंबकीय कोर हैं, जो पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड हैं। वे सामग्रियों के एक वर्ग से संबंधित हैं जो लौहचुंबकत्व की तकनीकी रूप से लागू संपत्ति को प्रदर्शित करते हैं। लौहचुंबकीय पदार्थ में, चुंबकत्व बाहरी रूप से लागू क्षेत्र के तहत होता है। इस क्षेत्र को हटाने पर, सामग्री अपनी गैर-चुंबकीय स्थिति में वापस आ जाती है। इस व्यवहार को चुंबकीय रूप से "नरम" कहा जाता है।
- 4. सॉफ्ट फेराइट कोर सिरेमिक यौगिकों से बड़े पैमाने पर फेरिक ऑक्साइड (Fe2O3) को मिलाकर, दबाकर, निकालकर और फायर करके स्ट्रोंटियम, बेरियम, मैंगनीज, निकल और जस्ता जैसे एक या अधिक अतिरिक्त धातु तत्वों के छोटे अनुपात के साथ मिश्रित करके बनाए जाते हैं। . सॉफ्ट फेराइट कोर के सबसे सामान्य रूप मैंगनीज-जिस्ता जिंक फेराइट (MnZn) और निकेल-जिंक फेराइट (NiZn) हैं। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मैंगनीज-जस्ता आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर तक सीमित है।
- 5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण होने वाले उच्च आवृत्ति शोर स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। वे विभिन्न उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की ज्यामिति में उपलब्ध हैं। उनकी उच्च चुंबकीय पारगम्यता और कम विद्युत चालकता के कारण, वे आरएफ ट्रांसफार्मर, स्विच मोड पावर सप्लाई (एसएमपीएस) और फेराइट लूप स्टिक एंटेना जैसे अनुप्रयोगों में सुसज्जित हैं। इनका उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर, मोबाइल चार्जर, एलईडी ड्राइवर, दूरसंचार उपकरण, सौर पैनल आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- 6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची I के टैरिफ आइटम 85051110 "फेराइट कोर" के तहत आयात किया जाता है। मा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- 7. आवेदक ने वर्तमान जांच में उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित नहीं किया है। हालाँकि, इच्छुक पक्ष इस जाँच के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित पीयूसी/पीसीएन पर इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव दे सकते हैं।

ख समान वस्त्

- 8. आवेदक ने दावा किया है कि जिन संबद्ध वस्तुओं को भारत में डंप करने का आरोप लगाया गया है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तु और विषय देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि अनुप्रयोग की दृष्टि से ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को प्राधिकरण द्वारा विषय देश से आयात किए जा रहे विषय वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।
 - ग. संबद्ध देश
- 9. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन.गण.है।
 - घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति
- 10. आवेदन कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध वस्तु के तीन अन्य भारतीय उत्पादक हैं, अर्थात् टीडीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया और डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया के संबंध में, आवेदक ने दावा किया है कि वह अपने कैप्टिव

उपयोग के लिए संबद्ध वस्तुओं के अपने स्वयं के उत्पादन का लगभग 30% उपयोग करता है। आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि टीडीके इंडिया प्रा. लिमिटेड, टीडीके चाइना कंपनी लिमिटेड से संबंधित है, जो चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। टीडीके चाइना कंपनी लिमिटेड ने भी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इस प्रकार, टीडीके इंडिया प्रा. लिमिटेड को नियम 2(बी) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए और इसके उत्पादन को पात्र घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

11. आवेदक ने दावा किया है कि उसने संबद्ध देश से बहुत कम मात्रा में संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इसका संबद्ध देश के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा किए गए आयात की जांच की है और नोट किया है कि कुल भारतीय उत्पादन, भारतीय मांग, देश में कुल आयात और अपने स्वयं के उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किए गए स्व-आयात का हिस्सा नगण्य है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया आवेदक को विषय वस्तु का पात्र घरेलू उत्पादक माना है। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन नियम 2(बी) के संदर्भ में कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है और एडी नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में भी खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ कथित इंपिंग का आधार

- i. सामान्य मूल्य
- 12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) और एडी नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार, चीन जन.गण. के उत्पादकों का सामान्य मूल्य लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है या चीन जन.गण. में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमतें केवल तभी होती हैं जब चीन जन.गण. से प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमों के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमित देती है, असफल होने पर चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 13. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या कीमत से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को समायोजित करने के बाद उपलब्ध विषय वस्तु के भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।
- ii. निर्यात कीमत
- 14. आवेदक ने निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार खुफिया जानकारी के अनुसार रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत का दावा किया निर्यात मूल्य को समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल ढुलाई व्यय, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के साथ समायोजित किया गया है।
- iii. पाटन मार्जिन
- 15. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है।
- च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध
- 16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग पर डंप, कीमत में कटौती और कीमत दबाने के प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदक ने भौतिक क्षति के एक और खतरे का भी दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है और संबद्ध देश से कथित डंप आयात के कारण क्षति का और खतरा है।
- छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत
- 17. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, मूल या निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के बारे में खुद को संतुष्ट किया

है। संबद्ध देश, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित डंपिंग और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकरण, अस्तित्व, डिग्री निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू करता है। और विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित डंपिंग का प्रभाव और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ज. जांच की अवधि

18. वर्तमान जांच की जांच अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 माह) है। चोट की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 और POI होगी।

झ. प्रक्रिया

- 19. वर्तमान जांच में एडी नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।
- ञ. सूचना प्रस्तृत करना
- 20. सभी संचार प्राधिकरण को ईमेल पते adgl6-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jdl6-dgtr@gov.in, और dd15-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबिमशन का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में है और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हैं।
- 21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है तािक वे सभी दस्तावेज दािखल कर सकें। इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रासंगिक जानकारी। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, एडी नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
- 22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से जांच से संबंधित अपने प्रस्तुतीकरण कर सकता है।
- 23. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को उसका एक गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 24. इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित नजर रखें।
 - ट. समय सीमा
- 25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राधिकरण को ईमेल पते adgl6-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jdl6-dgtr@gov.in, और dd15-dgtr@ पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। gov.in उस तारीख से तीस दिनों के भीतर जिस दिन इसे प्राधिकरण द्वारा भेजा गया था या एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण एडी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
- 26. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
- 27. जहां कोई इच्छुक पक्ष सबिमशन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियमों के नियम 6(4) के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।
 - ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तृत करना
- 28. जहां वर्तमान जांच का कोई भी पक्ष प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां देता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, उसे एडी नियमों के नियम 7(2) के संदर्भ में ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय

- संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।
- 29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (उससे जुड़े परिशिष्ट/परिशिष्ट सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
- 30. प्रस्तुतियाँ प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित होनी चाहिए। ऐसे चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किया गया कोई भी सबिमशन प्राधिकरण द्वारा "अगोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे सबिमशन का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 31. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसके बारे में प्रकृति द्वारा गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उस जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
- 32. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त किया जाना चाहिए (यदि अनुक्रमणिका संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर सारांशित किया जाए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
- 33. गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के सार को उचित ढंग से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पार्टी यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और एडी नियमों के नियम 7 और जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण। प्राधिकरण, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
- 34. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।
- 35. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या एडी नियमों के नियम 7 के संदर्भ में उचित कारण विवरण के बिना और गोपनीयता दावे पर उचित व्यापार नोटिस के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
- 36. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।
 - ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
- 37. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी प्रस्तुतियों का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करने का अनुरोध भी किया जाएगा
 - ढ. असहयोग
- 38. ऐसे मामले में जहां कोई इच्छुक पार्टी उचित अविध के भीतर या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंचने से इनकार करती है और अन्यथा प्रदान नहीं करती है, या जांच में काफी बाधा डालती है, तो प्राधिकरण ऐसी इच्छुक पार्टी को असहयोगी घोषित कर सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है। अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालना और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें करना जो उचित समझी जाएं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

Case No. AD(OI)-(21/2023)

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Soft Ferrite Cores" originating in or exported from China PR.

- **F. No. 6/22/2023-DGTR.** 1. Cosmo Ferrites Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "AD Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Soft Ferrite Cores" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").
- The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India, originating in or exported from
 the subject country at dumped prices in significant quantities causing material injury and threat of material
 injury to it and has requested for imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the
 subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 3. The product under consideration in the present investigation is "Soft Ferrite Cores" originating in or exported from China PR. Ferrite cores are magnetic cores made of ferrites, which are polycrystalline oxides. They belong to a class of materials that exhibit the technically applicable property of ferromagnetism. In a ferromagnetic material, magnetism occurs under an externally applied field. On removals of this field, the material returns to its non-magnetic state. This behaviour is termed as magnetically "soft".
- 4. Soft Ferrites Cores are made from ceramic compounds by mixing, pressing, extruding, and firing large proportions of ferric oxide (Fe2O3) blended with a small proportion of one or more additional metallic elements such as strontium, barium, manganese, nickel, and zinc. The most common forms of Soft Ferrite Cores are Manganese-zinc ferrite (MnZn) and Nickel-zinc ferrite (NiZn). The product under consideration in the present investigation is limited to Manganese-Zinc-based Soft Ferrite Cores.
- 5. The product under consideration is used to attenuate high-frequency noise levels caused by electronic devices. They are available in a variety of geometries to make them suitable for different industries. Owing to their high magnetic permeability & low electrical conductivity, they are equipped in applications, such as RF transformers, switch mode power supplies (SMPS) & ferrite loop stick antennas. They are used in several applications, including but not limited to, electric vehicles, electric vehicle chargers, mobile chargers, LED drivers, telecommunication devices, solar panels etc.
- 6. The product under consideration is imported under tariff item 85051110 "Ferrite Cores" of the first schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition.
- 7. The applicant has not proposed the Product Control Numbers (PCNs) in the present investigation. The interested parties, however, can provide their comments/suggestions on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences between the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers are using the two interchangeably. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable from the point of view of applicant. Hence, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the application are being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

9. The subject country in the present investigation is China PR.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 10. The application has been filed by Cosmo Ferrites Limited. The applicant has stated that there are three other Indian producers of the subject goods namely, TDK India Pvt. Ltd., CIE Automotive India and Delta Manufacturing Limited. With respect to CIE Automotive India, the applicant has claimed that it uses approximately 30% of its own production of the subject goods for its captive use. It has also been claimed by the applicant that TDK India Pvt. Ltd., is related to TDK China Co., Ltd., which is engaged in the production and sales of the subject goods in China. TDK China Co., Ltd. has also exported the subject goods to India. Thus, TDK India Pvt. Ltd. should not be considered as an eligible domestic industry as per Rule 2(b) and its production should not be included in the eligible domestic production.
- 11. The applicant has claimed that it has imported a minuscule quantity of the subject goods from the subject country and is not related to any exporter or producer from the subject country or any importer in India. The Authority has examined the imports made by the applicant and notes that the share of self-imports made by the applicant during the POI in terms of the total Indian production, Indian demand, total imports in the country and its own production and sales is negligible. Keeping in view these aspects, the Authority has *prima facie* considered the applicant as an eligible domestic producer of the subject goods. The Authority notes that the production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production in terms of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

E. BASIS OF ALLEGED DUMPING

i. Normal Value

- 12. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure I to the AD Rules, the normal value of producers of China PR may be determined based on the costs or domestic selling prices prevailing in China PR only if the responding producers from China PR demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules.
- 13. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as available after adjusting the selling, general and administrative expenses with a reasonable profit margin.

ii. Export Price

14. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for the determination of export price. The export price has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

iii. Dumping Margin

15. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury as a result of dumped, price undercutting and price suppressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted. The applicant has also claimed a further threat of material injury. The Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered material injury and a further threat to injury due to the alleged dumped imports from the subject country.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

17. On the basis of the duly substantiated written application filed by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree

and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

18. The period of investigation for the present investigation is from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury investigation period will be 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022 and the POI.

I. PROCEDURE

19. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

- 20. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses adgtr@gov.in, idl6-dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
- 21. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.
- 22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority within the time-limit mentioned in this initiation notification.
- 23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

- 25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, idl6-dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in within thirty days from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per of Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
- 26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
- 27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

- 28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
- 29. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
- 30. The submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
- 31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the

supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

- 32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 33. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receipt of the non-confidential version of the documents.
- 34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

38. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority